*वैश्विक अर्थव्यवस्था: चुनौतियां, अवसर और आगे का रास्ता**

श्री शक्तिकान्त दास

भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) और फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप्स (एफडब्ल्यूजी) कार्यधाराओं के भाग के रूप में आज की संगोष्ठी के विषय वैश्विक अर्थव्यवस्था: चुनौतियां, अवसर और आगे का रास्ता में तीन पैनल चर्चाओं सहित (i) विकास और वैश्विक सार्वजनिक हितों के वित्तपोषण; (ii) वैश्विक ऋण की कमज़ोरियों से निपटना; और (iii) वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम पर समृद्ध और अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार सामने आए हैं। । ये सभी मुद्दे भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताएं हैं। आज की चर्चाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद देता हूं।

आज दुनिया भर के नीति निर्माता उच्च मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार की कमजोरियों, कम नीतिगत गुंजाइश और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद महामारी के बाद की बहाली सुनिश्चित करने में बहुआयामी और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इस परिवेश में भारत की जी-20 अध्यक्षता का उद्देश्य ऐसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है। यह वसुधैव कुटुम्बकम के अध्यक्षीय विषय में सन्निहित है - "एक पृथ्वी • एक परिवार • एक भविष्य"। यह विषय सभी की समान समृद्धि के लिए वैश्विक सार्वजनिक हित के महत्व को रेखांकित करता है।

वैश्विक जन सुविधाएं (ग्लोबल पब्लिक गुड्स (जीपीजी)) विकासशील रणनीतियों को आकार देने और सभी देशों और दीर्घ समय के लिए मानव कल्याण को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कोविड-19 महामारी, अत्यधिक अस्थिर भू-राजनीतिक वातावरण, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में बाधाएं, वित्तीय बाजार की स्थितियों और वैश्विक चलनिधि में महत्वपूर्ण बदलाव के मद्देनजर उनका वित्तपोषण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इन सभी कारकों को एक साथ देखते हुए वैश्विक वित्तीय स्थिरता वैश्विक सार्वजनिक हितों के पदानुक्रम में प्रमुखता प्राप्त कर रही है।

भारत के अनुभव से पता चलता है कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का उपयोग लागत में कटौती के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है। इंडिया स्टैक और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में हमारे निरंतर कार्य से, विशेष रूप से महामारी के दौरान और उसके बाद, यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि यूपीआई जैसा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय सीमाओं से परे पहुंचने पर ग्लोबल पब्लिक गुड्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

हालांकि यूपीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाली पहल रही है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि सार्वजनिक हितों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विकसित और वित्तपोषित किया जाए। निजी क्षेत्र को ग्लोबल पब्लिक गुड्स (जीपीजी) के प्रावधान में शामिल होने की आवश्यकता है। ऐसा केवल इसलिए नहीं कि वे व्यवसायों को पनपने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रयास होंगे। इस संबंध में, ऐसे अभिनव डिजाइन सुविधाओं का निर्माण करना सार्थक होगा जो निजी निवेशकों को जीपीजी के वित्तपोषण में आकर्षक लगता हो। चूंकि इसमें बहुत बड़ी निवेश आवश्यकता है, क्रमिक वित्तपोषण में शुरुआती वित्तपोषण सार्वजनिक निवेश से आ सकता है। इससे जोखिम को कम करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी। बाद की वित्तपोषण आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र द्वारा पूरा किया जा सकता है। यह एक ऐसा अवसर है जहां अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और उतार-चढ़ाव महत्व रखते हैं। इसलिए, ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए निजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने में जोखिम साझाकरण एक महत्वपूर्ण डिजाइन तत्व होना चाहिए। इस प्रयास में, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक (एमडीबी) जोखिम साझाकरण तंत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

वैश्विक सहयोग में हाल की खामियों के कारण ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए कम प्रावधान हुआ है और आर्थिक कल्याण का क्षरण हुआ है। कोविड-19 टीकों तक निर्बाध पहुंच का अभाव

* 11 अगस्त 2023 को मुंबई में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित ग्लोबल इकॉनोमी: चैलेंजेस, एपोर्चनिटीज़ एंड वेज़ फॉरवर्ड विषय पर संगोष्ठी में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का समापन भाषण।

एक उदाहरण है। इसी तरह, समय पर वित्तीय सहायता और लेनदार सहयोग की कमी, भले ही आंशिक रूप से, कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते ऋण तनाव की व्याख्या कर सकती है। उच्च और अस्थिर ऋण स्तर ने कई देशों को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिससे उनकी राजकोषीय क्षमता सीमित हो गई है। हालांकि जी-20 के नेतृत्व वाली पहलों, जैसे कि ऋण प्रक्रिया के लिए कॉमन फ्रेमवर्क (सीएफ) और डेट सर्विस सस्पेंशन इनीशिएटिव (डीएसएसआई) पर गहन चर्चा की गई है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण प्रगति अभी हासिल की जानी है। मैं इस संदर्भ में तीन विशिष्ट सुझाव देना चाहूंगा।

सबसे पहले, यह आवश्यक है कि देशों के लिए डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस (डीएसए) संवृद्धि के संबंध में यथार्थवादी हो और राजकोषीय अनुमान पूरी तरह से सटीक और व्यापक ऋण डेटा पर आधारित हों। एक वैश्विक ऋण डेटा-साझाकरण मंच इस संबंध में मदद कर सकता है। इस तरह के मंच की स्थापना करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसमें कई साल लग सकते हैं। इसलिए, इस बीच, हम ऋण प्रवाह के लिए उपयुक्त प्रॉक्सी के निर्माण की संभावना की जांच कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (आईआईएफ) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) जैसे स्रोतों से पूंजी प्रवाह और स्थानीय बैंकिंग आंकड़ों पर डेटा से प्राप्त किए जा सकते हैं।

दूसरा, कम आय वाले ऐसे देश जिनका ऋण बहुत अधिक है उन्हें लक्षित सहायता प्रदान करने वाले बहुपक्षीय ऋण राहत कार्यक्रम पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। इस पहल को शाश्वत विकास परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन प्रयासों के लिए ऋण राहत के उपयोग पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ डिजाइन किया जा सकता है। इसके लिए, डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप्स[1] और ग्रीन डेट रिलीफ प्रोग्राम[2] जैसे साधनों को नियोजित किया जा सकता है।

तीसरा, वैश्विक ऋण कमजोरियों को दूर करने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये संस्थान अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के केंद्र में हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वे ऋण संकट में फंसे देशों के लिए और अधिक काम करें। वर्तमान में, आईएमएफ के एहतियाती कार्यक्रम जैसे कि प्रिकॉशनरी लेंडिंग लाइन ऐसे देशों के लिए उपलब्ध हैं जिनका व्यापक बुनियादी ढांचा मजबूत है। लेकिन मजबूत व्यापक बुनियादी ढांचे वाले देशों के लिए एहतियाती सुविधाओं की मदद लेने के बहुत कम कारण हैं। इसके अलावा, भुगतान संतुलन संकट वाले देशों के लिए स्टैंड-बाय व्यवस्था (एसबीए) की पेशकश की जाती है; लेकिन एसबीए की सुविधा निर्धारित प्रदर्शन और कमी के प्रकार को देखते हुए दी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हाल के अनुभव से पता चलता है कि आईएमएफ कार्यक्रमों तक पहुंच के कथित नकारात्मक स्थिति / या कमी के कारण देशों को ऋण शाश्वतता परिणामों के साथ आईएमएफ के बजाय अन्य उधारदाताओं से समर्थन लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यह उपयोगी होगा यदि ऐसे देशों के लिए जो मजबूत व्यापक बुनियादी ढांचे वाले नहीं हैं लेकिन यथोचित रूप से समुत्थानशील हैं और भुगतान संतुलन तनाव से प्रभावित नहीं हैं उनके लिए कम शर्तों के साथ डिज़ाइन कार्यक्रम तैयार किया जाए।

मैं जिस मुख्य बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि वित्तपोषण सहित सुधारात्मक उपायों को समय पर, बिना किसी कमी को चिह्नित करते हुए और अधिक खुली पहुंच के आधार पर रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, एक बड़ा और मजबूत आईएमएफ जो देश के जोखिम स्तर का प्रबंधन करने में सक्षम है, विशेष महत्व रखता है। चूंकि आईएमएफ का समर्थन देशों के कोटा आकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोटा की 16 वीं सामान्य समीक्षा और अभिशासन सुधार सहित इसकी वर्तमान आवश्यकताओं को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की निगरानी में आईएमएफ की तर्कसंगतता बढ़ाने के अलावा, इससे आईएमएफ की नीतिगत सलाह का प्रभाव भी बढ़ेगा। हमें ऋण के बोझ के कारण वैश्विक विकास की क्षमता को कम नहीं होने देना चाहिए।

इस संबंध में, वैश्विक विकास के लिए प्रमुख जोखिमों, अर्थात् मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन पर पैनल

[1] ऋण स्वैप के माध्यम से कम कार्बन और जलवायु-समुत्थानशील अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण करने वाले देशों का समर्थन करना जो ऋण राहत को पर्यावरण के अनुकूल नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जोड़ते हैं।

[2] ऋणदाता पर्यावरणीय शाश्वतता, सामाजिक विकास और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं में निवेश के बदले में ऋण में कटौती या राइट-ऑफ की पेशकश करते हैं।

चर्चा सामयिक प्रासंगिकता रखती है। भले ही वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण निम्नगामी जोखिम से प्रभावित है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसी दीर्घकालिक संरचनात्मक चुनौतियों को हरित संक्रमण के लिए पर्याप्त और किफायती वित्तपोषण की आपूर्ति के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

हालांकि, हमें हरित संक्रमण के संभावित वित्तीय स्थिरता प्रभावों के प्रति सावधान रहना चाहिए। संक्रमण के प्रयासों में जलवायु परिवर्तन के भौतिक और संक्रमण दोनों जोखिमों से निपटने का प्रावधान होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और विकास क्षमता के नुकसान से बचने के लिए सुचारु और व्यवस्थित हरित संक्रमण आवश्यक है। एक ओर जहां सुचारु हरित संक्रमण के लिए निवेश की आवश्यकताएं बड़ी हैं, वहीं हरित परियोजनाओं के लिए वास्तविक वित्तीय प्रवाह अत्यधिक विषम हैं और कुल मिलाकर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित हैं। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में हरित पूंजी प्रवाह को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। आईएमएफ ने हाल ही में वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ग्रीन रेटेड निवेश परियोजनाओं की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण ईएमडीई के लिए हरित प्रवाह कम हो जाता है। जबकि आज हरित प्रवाह पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) रेटिंग पर निर्भर हैं, हाल के शोध से पता चलता है कि ये ईएसजी रेटिंग इन निवेशों की वित्तीय और गैर-वित्तीय भौतिकताओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि "ग्रीन रेटिंग" परियोजनाओं के वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाती हैं ताकि हरित पहलों संबंधी गलत बयानी (ग्रीन-वॉशिंग) से बचा जा सके।

इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू वैश्विक स्तर पर तुलनीय और पारदर्शी प्रकटीकरण मानदंडों और हरित गतिविधियों के वर्गीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन प्रयासों के लिए निजी वित्तपोषण सुनिश्चित करना है। अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) इन पहलुओं पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

जबकि हरित वित्तपोषण में सुधार और उसका प्रसार करने के प्रयास चल रहे हैं, विनियामकीय ढांचे को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो प्राधिकार क्षेत्रों में जलवायु वर्गीकरण के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है, ग्रीनवॉशिंग को रोकता है और ईएमडीई के लिए पर्याप्त हरित पूंजी प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। एक शाश्वत भविष्य की ओर सफल संक्रमण के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता को शामिल करते हुए एक व्यापक और सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है।

अब मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वैश्विक सार्वजनिक हितों के वित्तपोषण, वैश्विक ऋण कमजोरियों का प्रबंधन करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसी संरचनात्मक चुनौतियां कठिन कार्य हैं जिन्हें कोई भी देश अकेले पूरा नहीं कर सकता। बहुपक्षीय प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता जताना समय की मांग है और जी-20 की भारतीय अध्यक्षता ठीक इसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। भारत जैसे सदस्य देशों में हो रहे यूपीआई और वित्तीय समावेशन पहलों जैसे जन-केंद्रित परिवर्तनकारी कार्यों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मॉडलों को व्यापक रूप से अपनाने से दुनिया हर किसी के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है।

धन्यवाद।